

प्रेस विज्ञप्ति

4 जुलाई, 2018

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित बयान जारी किया :-

समर्थन मूल्य की 'जुमला वाणी' है – ऊँट के मुंह में जीरा,
वादा था, 'लागत+50%' समर्थन मूल्य का देंगे मौका,
अब कर रहे हैं, जुमले गढ़ अन्नदाता से धोखा।

मई, 2014 में झूठ की बुनियाद पर व 'लागत+50%' मुनाफा की जुमलावाणी कर मोदी जी ने देश के अन्नदाता किसान का समर्थन तो हासिल कर लिया, पर चार सालों से फसलों पर 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' की बिसात पर कभी खरे नहीं उतरे। अब हार की कगार पर खड़ी मोदी सरकार एक बार फिर 'राजनैतिक लॉलीपॉप' के नए जुमले गढ़ रही है। सच तो यह है कि किसान 49 महीने के 'मोदीकाल' में 'काल का ग्रास' बन गया है। न समर्थन मूल्य मिला, न मेहनत की कीमत। न कर्ज से मुक्ति मिली, न अथक परिश्रम का सम्मान। न खाद/कीटनाशक दवाई/बिजली/डीजल की कीमतें कम हुईं और न ही हुआ फसल के बाजार भावों का इंतजाम।

अन्नदाता किसान कह रहा है कि केवल 'जुमलों' और 'कोरी झूठ' से पेट नहीं भर सकता। क्या झूठी वाहवाही लूटने, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने, ऊँट के मुंह में जीरा डाल नगाड़े बजाने व समाचारों की सुर्खियां बटोरने से आगे बढ़ मोदी जी देश को जवाब देंगे :-

1. 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' (commission for agricultural costs and prices) की 2017-18 की सिफारिश के मुताबिक खरीफ फसलों की 'लागत+50%' की कीमत निम्नलिखित होनी चाहिए।

MSP for Kharif Crops

Crops	Cost of production (Rs. per Qtl.)	Cost+50% as per CACP recommendations for year 2017-18 (Rs/Qtl.)	MSP for Kharif 2018-19	Difference of MSP & Cost+50% (In Rs)
Paddy	1484	2226.00	1750	476
Jowar	2089	3133.50	2430	703.5
Ragi	2351	3526.50	2897	629.5
Maize	1396	2094.00	1700	394
Arhar	4612	6918.00	5675	1243
Moong	5700	8550.00	6975	1575
Urad	4517	6775.50	5600	1175.5

Ground Nut	4089	6133.50	4890	1243.5
Sunflower	4526	6789.00	5388	1401
Soyabean	2921	4381.50	3399	982.5
Cotton	4376	6564.00	5150	1414

आज घोषित खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 'लागत+50%' की शर्त को कहीं भी पूरा नहीं करता। यह किसान के साथ धोखा नहीं तो क्या है?

मोदी सरकार यह बताना तो भूल ही गई कि किसान को आज घोषित कीमत भी देश की अगली सरकार को देनी है, क्योंकि खरीफ 2019 बाजार में आने पर मोदी सरकार को तो जनता ने चलता कर दिया होगा।

अगर चार वर्षों में 'लागत+50%' मुनाफा सही मायनों में मोदी सरकार ने किसान को दिया होता, तो लगभग 200000 करोड़ रुपया किसान की जेब में उसकी मेहनत की कमाई के तौर पर जाता। परंतु यह मोदी सरकार आज बताना भूल गई।

2. मोदी सरकार जानबूझकर 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' की चालू साल 2018-19 की सिफारिशों को सार्वजनिक नहीं कर रही। आज मोदी मंत्रीमंडल ने खरीफ फसलों के मूल्यों की घोषणा कृषि मूल्य आयोग द्वारा पिछले साल, यानि 2017-18 के लागत मूल्य आंकलन को ध्यान में रखकर की है, न कि कृषि मूल्य आयोग के मौजूदा साल यानि 2018-19 के लागत मूल्य आंकलन के आधार पर। **किसान के साथ यह धोखाधड़ी क्यों?**

20 जून, 2018 को नमो ऐप पर किसानों से बातचीत करते हुए खुद मोदी जी ने 'लागत+50%' का आंकलन 'C2' के आधार पर देने का वादा किया (<http://www.hindkisan.com/video/pm-modis-interaction-with-farmers-via-namo-app/>)। स्पष्ट तौर पर कहा कि किसान के मजदूरी व परिश्रम + बीज + खाद + मशीन + सिंचाई + ज़मीन का किराया आदि शामिल किया जाएगा। **फिर वह वायदा आज जुमला क्यों बन गया?**

3. मोदी सरकार ने लागत निर्धारित करते वक्त कुछ मूलभूत बातें पूर्णतया दरकिनार कर दीं। जैसे कि :-

- 16 मई, 2014 को डीज़ल की कीमत ₹ 56.71 रु. प्रति लीटर थी। यह लगभग ₹11 प्रति लीटर बढ़कर आज ₹ 67.42 रु. हो गई है।
- यहां तक कि पिछले 6 महीने में खाद की कीमतें बेलगाम हो 24 प्रतिशत तक बढ़ गईं।
بيخ تحوط بديجیٹل खाद का 50 किलो का कट्टा जनवरी, 2018 में ₹ 1091 में बेच रहा था, जो आज बढ़कर ₹ 1290 प्रति 50 किलो हो गया है। हर साल किसान 89.80 लाख टन بیخ تحوط खरीदता है, यानि उसे ₹5561 करोड़ की चपत लगी।
- कीटनाशक दवाई हों, बिजली हो, सिंचाई के साधन हों या खेती के उपकरण, उन सबकी

कीमतें बेतहाशा बढ़ गईं।

4. 70 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसान और खेती पर टैक्स लगाने वाली यह पहली सरकार है। खाद पर 5 प्रतिशत जीएसटी, ट्रैक्टर/कृषि उपकरणों पर 12 प्रतिशत जीएसटी, टायर/ट्यूब/ट्रांसमिशन पार्ट्स पर 18 प्रतिशत जीएसटी, कीटनाशक दवाइयों पर 18 प्रतिशत जीएसटी, कोल्ड स्टोरेज इक्विपमेंट पर 18 प्रतिशत जीएसटी।

5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बनकर रह गई। बीमा कंपनियों को 14,828 करोड़ का मुनाफा हुआ, जबकि किसान को मुआवजे के तौर पर मिला केवल 5,650 करोड़।

फसल मौसम	प्रीमियम भुगतान (करोड़ रु. में)	मुआवजा भुगतान (करोड़ रु. में)	कंपनियों को हुआ लाभ (करोड़ रु. में)
खरीफ 2016 + रबी 2016-17	20,478	5,650	14,828

6. कृषि निर्यात औंधे मुंह गिरा और आयात बढ़ा। किसान मुसीबत में और माफिया की पौ बारह। यही मोदी सरकार की असली कहानी है। किसान पर दोहरी मार यह है कि कृषि निर्यात में 9.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आई और कृषि आयात 10.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ गया। यानि किसान को 19.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ।

कृषि आयात/निर्यात तालिका		मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में		
साल	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
निर्यात	43.23	39.06	32.79	33.87
आयात	15.03	20.62	22.06	25.09